मोयली की पेट्रोल किफ़ायत या नुस्खा-ए-आफत

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

पैट्रोलियम आयात बिल घटाने के नाम पर पैट्रोलियम मन्त्री विरप्पा मोयली कोई ढंग का काम करने की बजाय ऊट-पटांग बातें करने में जुटे हैं। गत माह उन्होंने सुझाया था कि रात को पैट्रोल पम्प बन्द रखे जायं। अब कोई पूछे इस अक्ल के दुश्मन से कि रात को पम्प बन्द रखने से उन वाहनों का क्या होगा जो रात में चलतें हैं? यदि पम्प बन्द ही रखने हों तो रात को सड़कें भी बंद कर देनी चाहिये, खैर वे तो उस हालत में अपने आप ही बन्द हो जायेंगी। शुक्र है प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मूर्खतापूर्ण सुझाव को सिरे से ठुकरा दिया।

दूसरा सुझाव उन्होंने यह दिया है कि सरकारी कारों में जाने वाले तमाम मन्त्री-संतरी सप्ताह में एक दिन बसों से दफ़्तर जाया करें। एक दिन क्यों? रोज़ाना क्यों नहीं? रोज़ाना कार में सफ़र करने वाले के लिये एक दिन बस में चलना कहीं ज़्यादा कठिन होता है। यदि तमाम सरकारी कारों को बन्द करके सभी के लिये सार्वजनिक वाहनों में चलना अनिवार्य कर दिया जाय तो इससे तेल तो बचेगा सो बचेगा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भारी सुधार हो जायेगा। आम आदमी जो आज इस परिवहन व्यवस्था को भुगत रहा है और सरकार सुनती नहीं, वह स्वत: ठीक हो जायेगी जब सरकार स्वंय इसमें चलने लगेगी। मोयली का सुझाव मात्र एक दिन बस में बैठ कर फ़ोटो खिंचवाने तक का लगता है।

यदि मोयली एवं तमाम शासक वर्ग की नीयत सही है और वे वास्तव में ही पैट्रोलियम खपत को घटाना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे उपाय है जिनके द्वारा यह काम बड़ी सरलता से हो सकता है। प्रत्येक सरकारी दफ़्तर, जहां हरामखोर अफ़सर/बाबू काम करके राज़ी नहीं, उन्हें काम करना सिखाया जाय। किसी से छिपा नहीं है कि जो काम एक पत्र अथवा आवेदन मात्र से हो जाना चाहिये, वह तब तक नहीं होता जब तक सम्बन्धित व्यक्ति दफ़्तर की हर टेबल पर जाकर अपनी फ़ाइल को न चलवाये। अकेले इसी शहर से रोज़ाना हज़ारों लोग बसों व कारों से अपने काम निकलवाने सुबह-सुबह चंडीगढ भागते हैं और रात को या अगले दिन वापस लौटते हैं। एक चंडीगढ नहीं हर शहर व कस्बे से लोगों को वहां भागना पड़ता है जहां उसका काम सम्बन्धित बाबू कर नहीं रहे। राज्य के विश्वविद्यालयों खासकर एम डी यू रोहतक में तो कोई काम तब तक होता ही नहीं जब तक सम्बन्धित बाबू की टेबल पर जाकर 'ग्रीस' न लगाई जाये। यदि ये सरकारी दफ़्तर सही ढंग से काम करने लग जायें तो सड़कों पर का यातायात स्वत: घट कर आधा रह जायेगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों की सरकार ने रिश्वत व भाई-भतीजावाद के आधार पर जो हर दफ़्तर में चोर बैठा रखे हैं वे भला ऐसा क्यों करने लगे?

इसके अलावा तेल की बर्बादी का दूसरा बड़ा कारण है सड़कों की दुर्दशा। सपाट और बढिया सड़क पर चलने से जो सफ़र एक घंटे में पूरा होता है वह टूटी-फूटी एवं गड्ढेदार सड़कों पर दो या इससे भी अधिक समय में पूरा हो पाता है। इसमें तेल के अलावा वाहन का जो नुकसान होता है वह अलग से। इसके अलावा सड़कों पर बेमतलब के जाम भी काफ़ी तेल बर्बाद करते हैं। किसी दुर्घटनावश, कहीं-कहीं कभी-कभार जाम लगना तो समझ आता है, लेकिन सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़े कर देना, सड़क पर सामान रख कर या अन्य तरह से अतिक्रमण कर लेना, और कुछ नहीं तो आस्था एवं धर्म की दुकानदारी के नाम पर सड़कों पर भजन-कीर्तन आदि का जुलूस निकालना समझ से परे है। चन्द लोगों की आस्था के पीछे सैंकड़ों हज़ारों वाहन चलने के बजाय रेंगने को मजबूर हो जाते है। इन सबको रोका जा सकता है एक सख्त यातायात अनुशासन के द्वारा। परन्तु यह कामचोरों की वह सरकार कभी नहीं कर सकती जो भीतर से खोखली हो। वह कड़े कदम उठाने से सदैव घबराती है।

मोयली तो जुम्मा-जुम्मा अभी आये हैं। इनसे पहले वालों ने कौन सा कभी तेल आयात की समस्या को गंभीरता से लिया है? यदि देश के नेता इस देश से दुश्मनी न निकाल रहे होते और अपनी जेबें भरने मात्र के लिये काम न करते तो रेलवे में डीज़ल इंजन और वे भी पांच-पांच हज़ार हार्सपावर के, जबकि भारतीय सवारी-गाड़ियों में हज़ार से डेढ हज़ार हार्सपावर तक के इंजन ही पार्याप्त होते हैं। दरअसल ये इंजन केवल इस लिये आयात किये गये थे कि निर्यातक विकसित देशों को तब इनकी जरूरत नहीं रह गयी थी। इधर भारतीय नेताओं को मोटा कमीशन मिल जाये तो फ़िर कुछ भी चेप दो इनको। जिस दौर में डीजल इंजन खरीदने की शुरूआत भारत में हुई थी, उस वक्त विकसित देश बिजली के इंजनों पर आ गये थे, इसलिए उनके डीज़ल इंजन बेकार हो गये थे उस वक्त भारतीय रेल के वरिष्ठ एवं निष्ठावान अफ़सरों ने इन डीज़ल इंजनों के आयात का विरोध करते हुए सीधे बिजली के इंजन लाने की बात कही थी तथा इसके लिये रेलवे के ही, बिजली आपूर्ति हेतु अपने खुद थर्मल प्लांट लगाने का सुझाव दिया था। इसके लिये पर्याप्त संसाधन देश में उपलब्ध होने के बावजूद विद्युतीकरण की अपेक्षा डीज़ल इंजन खरीद का निर्णय लिया गया जबकि डीज़ल आयात करना पड़ता है।

आयात भी अमेरिकी दबाव में डॉलर देकर करना पड़ता है। उस देश (ईरान) से नहीं खरीद सकते जो रुपये या गेहूं के बदले तेल देने को तैयार हो। वहां से गैस पाइप लाइन का काम भी केवल अमेरिकी दबाव में रुका पड़ा है। यदि वहां से गैस आपूर्ति चालू हो जाये तो देश की उर्जा समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है।

देश के अपने गैस भंडार इस सरकार ने अंबानी (रिलांयस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड) को दान में दे दिये हैं। इन पर वह कुंडली मार कर बैठा है। उसे ये भंडार देते वक्त समझौता हुआ था कि वह इस गैस को 2 डॉलर प्रति यूनिट इस देश को देगा। इसके लिये उत्पादन क्षमता भी निर्धारित की गयी थी। लेकिन इसने न तो निर्धारित मात्रा में उत्पादन किया और न ही 2 डॉलर के भाव पर कायम रहा। कम्पनी के हित में सरकार ने यह भाव बढ़ाकर दो से चार और फ़िर आठ डॉलर भी कर दिया तो भी उसने आवश्यक मात्रा में उत्पादन नहीं किया। उसकी मांग अब 16 डॉलर की है।

अंबानी द्वारा समझौता तोड़ने के एवज में जब पूर्व तेल मंत्री जयपाल रेड्डी ने डरते-डरते 70 हज़ार करोड़ की जगह मात्र 7 हज़ार करोड़ रुपये का जुर्माना अंबानी पर लगाया तो बेचारे रेड्डी को इस मन्त्रालय से हाथ धोना पड़ा और मोयली को जुर्माने वाली वह फ़ाईल 'मिल ही नहीं' रही। गत माह भी तेल मंत्रालय के डी जी हाइड्रोकार्बन ने इस पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया है जिस पर मोयली कुंडली मार कर बैठा है। बैठे क्यों नहीं आखिर नौकरी भी तो अंबानी की ही कर रहा है।

मोयली का टोटका

भारत सरकार के तेल व प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने नया शिगूफ़ा छोड़ा है कि सभी लोग एक दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें तो इससे सालाना 52 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इसलिये उन्होंने हर बुधवार 'बस डे' मनाना शुरू किया है जिससे तेल व गैस की बचत हो सके। उन्होंने इस बुधवार से मेट्रो से दफ़्तर जाना शुरू भी कर दिया और लोगों को बचत की नसीहत भी दे डाली। संदर्भवश बता दें कि इनके पूर्ववर्ती तेल मंत्री श्री जयपाल रेड्डी ने के.जी.डी.-6 क्षेत्र में अनुबंध से कम गैस उत्पादन के लिये 'रिलायंस' पर 7000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इन मोइली साहब को वह रिलायंस वाली फ़ाइल तो मिल नहीं रही, हां 52 करोड़ रुपए जैसी चिल्लर बचत की नसीहत जरूर दे रहे हैं। मोइली साहब अगले साल चुनाव है, जल्दी से फाइल ढूंढ लीजिए और ये जनता को चिल्लर से बहकाना छोड़कर रिलायंस से 7000 करोड़ रुपया वसूल कीजिये। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के वक्त आपकी भी वोटो वाली फ़ाईल जनता गायब कर दे और फ़िर एक दिन क्या सारे साल ही आप मेट्रों में धक्के खाते फ़िरें।

-अजातशत्रु

सुधी पाठकों से हमारा अनुरोध

'मज़दूर मोर्चा' को पढ़ने वाले सुधी पाठक भली-भांति समझते हैं कि यह एक पूर्णतया ग़ैरव्यवसायिक प्रयास है। आज की इस महंगाई के ज़माने में इसे नियमित निकालने की कठिनाइयों का अनुमान लगाना भी सुधी पाठकों के लिये कठिन नहीं होगा। इन कठिन परिस्थितियों में 'मज़दूर मोर्चा' को नियमित बनाये रखने के अलावा इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिये अनुरोध है कि डाक से प्राप्त करने वाले पाठक वार्षिक 100/-रुपया अथवा आजीवन 1000/- रुपया की सहयोग राशि 'मज़दूर मोर्चा' को भेजने की व्यवस्था करें। सहयोग राशि 'मज़दूर मोर्चा' कार्यालय 1डी/2 बी पी (हार्डवेयर चौक) एनआईटी फ़रीदाबाद के पते पर बजरिया मनीआर्डर अथवा चेक भेजी जा सकती है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ़ इन्डिया की किसी भी शहर की किसी भी ब्रांच में मज़दूर मोर्चा के खाता संख्या 451102010004150 में सीधे भी रकम डाली जा सकती है।

ज़िला फ़रीदाबाद व पलवल के पाठक अपनी प्रति अपने हॉकर से प्राप्त कर सकते हैं। पाठकों से यह भी अनुरोध है कि 'मजदूर मोर्चा' पढ़ने के बाद अपनी टिप्पणियां, आपत्तियां, सुझाव इत्यादि साधारण डाक, ई-मेल अथवा 9999595632 पर एसएमएस के द्वारा अवश्य भेजें। यह लेखन एवं सामग्री चयन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा।

- संपादक मंडल

तुर्की-ब-तुर्की

शरद यादव

जनता दल (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने 18 सितम्बर को जबलपुर में कहा, ''बेटी से बढ कर वोट की इज्जत है। बेटी की इज्जत जाती है तो परिवार व मोहल्ले की इज्जत जाती है परन्तु वोट की इज्जत जाती है तो देश की इज्जत जाती है। लिहाज़ा शराब व नोट के लिये ग़लत व्यक्तियों को वोट नहीं देना चाहिये।''

हमारा कहना है-

- लगे हाथ यह भी बता दीजिये कि चुनाव में सही व्यक्ति हैं कौन? वोटर को तो सांपनाथ और नागनाथ में से ही एक को चुनना होता है। अब अगर बीच में वह नोट और शराब ले ले तो क्या फ़र्क पड़ता है?
- हर बड़ी राजनीतिक पार्टी में टिकट पैसे देकर ही ख़रीदे जा रहे हैं। ऐसे में यह भी स्वाभाविक है कि वोट भी पैसे देकर ख़रीदे जाएं। जब आप जैसों ने राजनीति को धंधा बना ही दिया है तो धंधे के उसूल भी अपनी भूमिका निभायेंगे ही।
- आज के भ्रष्ट चुनावबाज़ों में से किसी को भी वोट देने मात्र से ही वोटर की अपनी इज्जत चली जाती है। ऐसा इस लिये कि उसे किसी न किसी चोर-डकैत के नाम पर ही मुहर लगानी पड़ती है। शुक्र है कि आइंदा एक नया बटन 'कोई पसंद नहीं' का भी आ गया है। अब कुछ वोटर इस बटन को दबा कर अपनी इज्जत तो बचा सकेंगे।
- और भला लड़की की 'इज्जत' जाने से आपका क्या मतलब है? इज्जत तो उस मर्द की जानी चाहिये जिसने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है। मर्द के परिवार व मोहल्ले की जानी चाहिये। आप जैसों की जानी चाहिये जो लड़की के सिर पर इज्जत का बोझा लादते हैं जिससे वह बलात्कार जैसी बर्बर हिंसा का शिकार बनती है और चुप रहने को मजबूर होती है।

साम्प्रदायिक किसे कहते हैं?

जो भी व्यक्ति या संगठन अपने धर्म और सम्प्रदाय के विचारों को दूसरे धर्म और सम्प्रदाय के विचारों से बेहतर मानता है और दूसरे धर्म और सम्प्रदाय के विचारों को अपने से बदतर मानता है, वह साम्प्रदायिक कहलाता है। वह नारी-जाति को जबरदस्ती गुलाम बनाये रखने का दुराग्रह करता है। वह तार्किक चिन्तन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध करता है। वह श्रेष्ठताबोध के भ्रम से ग्रस्त हो कर अपनी इस क्षुद्रतावादी अहंकारी सोच के चलते अपने विचारों को दूसरों पर जबरदस्ती थोपने के लिये दूसरे सम्प्रदाय का उपहास, अपमान और उत्पीड़न करता है। वह गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समाज की सारी समस्याओं के लिये केवल अपने विरोधी सम्प्रदाय को ही जिम्मेदार बताता है। इस तरह सभी सामाजिक समस्याओं का असली कारण-शोषक वर्गों द्वारा आम आदमी के वर्गीय शोषण को छिपाने के लिये वह धूर्तता के साथ धुएं की दीवार खड़ी करने की साजिश करता है। इस कुत्सा-प्रचार के चलते एक दूसरे के खिलाफ़ नफरत के गुस्से से लोगों को अन्धा बनाने वाली धार्मिक आस्थाओं के बीच मतभेद की यह तनातनी जब हद से बढ़ जाती है, तो साम्प्रदायिक संगठन साम्प्रदायिक दंगे करा के समाज में अपने आतंक के जरिये खौफ़ का माहौल पैदा करता है और फ़िर इन दंगों में बेगुनाह मासूम लोगों का वध करके प्रसन्न होता है। समाज में साम्प्रदायिक जहर फ़ैला कर शासक पूंजीपति वर्ग जनता के बीच के मनोमालिन्य की दरार को और चौड़ा करता है, जनता के बीच के सौजन्य और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ डालता है और फ़िर शोषण की चक्की को और तेज घुमाता चला जाता है। ऐसे मे फ़ासीवाद का दौर आता है जब शासक वर्ग द्वारा सभी जनतांत्रिक मूल्यों को कुचल कर केवल नंगी गुण्डई के सहारे जोर-जबरदस्ती की हुकूमत कायम की जाती है। फ़ासीवाद के दौर में राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों, पेशेवर गुण्डों, अपराधियों, माफ़िया और पुलिस व फ़ौज के दम पर शोषण, उत्पीड़न, दमन और अन्याय का विरोध करने का साहस करने वाले हर स्वर को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। अदालतों में न्याय के नाम पर केवल अन्याय होने लगता है। फ़ासीवाद अक्सर अल्पसंयक सम्प्रदाय के प्रति बहुसंख्यक सम्प्रदाय की नफ़रत को अपना औजार बनाता है। केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्रान्तिकारी विचारों से नयी पीढ़ी को लैस करके ही साम्प्रदायिकता के जहर से समाज को बचाया जा सकता है।

-गिरिजेश तिवारी